



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 2004/वैशाख 1, 1926

No. 90]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 2004/VAISHAKHA 1, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

न्यू शिपर समीक्षा अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2004

विषय :—मैसर्स सी एस बी बैटरी गुआंगझौ क. लि., चीन जनवादी गणराज्य के अनुरोध पर लैड एसिड बैटरियों के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा—अंतिम जांच परिणाम

क. प्रक्रिया: सं. 14/26/2002-डीजीएडी क. प्रक्रिया-1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० 14/26/2002-डी जी ए डी द्वारा उपर्युक्त नियमों के नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित मै० सी एस बी बैटरी गुआंगझौ कं० लि० द्वारा उत्पादित एवं मै० सी एस बी बैटरी, सिंगापुर द्वारा निर्यातित लैड एसिड बैटरियों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा शुरू की गयी थी ।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन की प्रारंभिक जांच करने पर कतिपय कमियां मालूम हुई थी जो बाद में याचिकाकर्ता द्वारा ठीक कर दी गयी थी । अतः याचिका को विधिवत प्रलेखित समझा गया था ।

2. इस न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाली चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित लैड एसिड बैटरियों के आयात के मामले में शुरू की गयी थी जिसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने 7 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I खंड I में प्रकाशित अपने अंतिम जांच परिणामों में यह निष्कर्ष निकाला था कि:

- (i) चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, जापान एवं बांग्लादेश से भारत को निर्यातित लैड एसिड बैटरियों का मूल्य जांच अवधि के दौरान उनके सामान्य मूल्य से कम है।
- (ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसे और वास्तविक क्षति होने का खतरा है।
- (iii) यह क्षति चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, जापान एवं बांग्लादेश से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित 2 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं. 1/2002 सीमाशुल्क द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

4. जैसा कि ऊपर कहा गया है मै0 सी एस बी बैटरी गुआंगझौ कं0 लि0, चीन जनवादी गणराज्य ने उनके द्वारा किए जा रहे निर्यातों के बारे में सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 22 के अनुसार एक समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया था और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड। में प्रकाशित 7 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 67/1/2000 - डी जी ए डी द्वारा 27 अगस्त, 2002 को समीक्षा शुरू की थी और मै0 सी एस बी बैटरी गुआंगझौ कं0 लि0, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के राजपत्र अनुसूची के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाली लैड एसिड बैटरियों के सभी निर्यातों की समीक्षा पूरी होने तक कालम सं0 5 में उल्लिखित राशि और प्रति किग्रा0 लैड एसिड बैटरियों के आयातों के पहुँच मूल्य के बीच अंतर के रूप में अनंतिम आकलन करने की सिफारिश की थी।

5. इसके अलावा, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 22 के उप नियम 27 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपरोक्त जांच परिणामों और दिनांक 2 जनवरी, 2002 की इसकी अधिसूचना सं0 1/2002 सीमाशुल्क पर विचार करने के पश्चात केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त समीक्षाओं का परिणाम घोषित किए जाने तक भारत में आयात करने पर मै0 सी एस बी बैटरी गुआंगझौ कं0 लि0, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा लैड एसिड बैटरियों के निर्यातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा और यह भी व्यवस्था की गयी थी कि भारत में आयात करने पर मै0 सी एस बी बैटरी गुआंगझौ कं0 लि0 चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित लैड एसिड बैटरियाँ अनंतिम मूल्यांकन के और कालम सं0 5 में उल्लिखित राशि और अधिसूचना सं. 110/2002 सीमाशुल्क के जरिए प्रति किग्रा0 लैड एसिड बैटरियों के आयातों का पहुँच मूल्य के बीच अंतर की दर पर परिकलित शुल्क की राशि की गारंटी के अध्वधीन होंगी।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त समीक्षाएं पूरी करने के पश्चात पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश के मामले में आयातक को मै0 सी एस बी गुआंगझौ कं0 लि0 चीन जनवादी गणराज्य से भारत में लैड एसिड बैटरियों के सभी आयातों पर लगायी गयी शुल्क की राशि का भुगतान उक्त समीक्षा प्रारंभ करने की तारीख से करने हेतु उत्तरदायी होना चाहिए।

7. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसरण में चीनी उत्पादक मै0 सी एस बी बैटरी कं0 लि0 चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके बाद संबंधित कंपनी कहा गया है) से 7 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 67/1/2000 की न्यू शिपर समीक्षा शुरू किए जाने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस कंपनी ने यह दावा किया था कि उसका संबंधित उत्पाद के संबंध में लागू पाटनरोधी उपायों के अध्यधीन चीन जनवादी गणराज्य में किसी निर्यातक उत्पादक से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, उसने यह भी दावा किया था कि उसने मूल जांच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या संबंधित चीनी उत्पादक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की थी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार एक समीक्षा शुरू करने के औचित्य के लिए उसे पर्याप्त समझा।

8. वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद वही है जो मूल जांच में है अर्थात् "लैड एसिड बैटरियाँ"।

9. प्राधिकारी ने एक निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के उनके दावे से संबंधित एक अतिरिक्त प्रश्नावली भी भेजी थी। निर्यातक ने प्रश्नावली को बढ़ायी गयी समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया था। प्राधिकारी ने पाटन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गयी सभी सूचनाएं मांगी थी और उनका सत्यापन किया था और संबंधित निर्यातक उत्पादक के परिसरों की जांच के लिए दौरा किया था।

10. चूँकि इस जांच में क्षति संबंधी जांच परिणामों की समीक्षा करने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया था इसलिए समीक्षा केवल पाटन के निर्धारण तक सीमित है।

11. पाटन की जांच में 1 सितम्बर, 2002 से 28 फरवरी, 2003 तक की अवधि शामिल है।

12. प्राधिकारी ने न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत करने हेतु निर्यातक देश के प्राधिकारियों को औपचारिक रूप से सूचित किया था और जांच अवधि (अर्थात् 1 सितम्बर, 2002 से 28 फरवरी, 2003 तक) की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने हेतु प्रत्यक्ष रूप से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया था। बाद में, प्राधिकारी ने 27 अगस्त, 2003 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिन्हें उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था।

13. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर उनके द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करायी।

14. प्राधिकारी ने मै0 सी एस बी, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का मौके पर सत्यापन किया।

15. उपर्युक्त पाटनरोधी नियमों के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार को 9/12/03 एवं 3/3/2004 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिखाया और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर इन जांच परिणामों में भी विधिवत रूप से विचार किया गया है।

16. XXX इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गयी सूचना का पता चलता है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

17. प्राधिकारी ने मूल मामले में लेड एसिड बैटरी के रूप में यथा निर्धारित विचाराधीन उत्पाद के वर्णन को जारी रखने का निर्णय किया है। चूँकि किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा समान वस्तु और विचाराधीन उत्पाद पर कोई तर्क नहीं दिया गया है अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित लेड एसिड बैटरी नियमानुसार, संबद्ध देशों से आयातित लेड एसिड बैटरी के समान वस्तु है।

18. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि मौजूदा जाँच में विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 85 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ 8507 के अंतर्गत वर्गीकरणीय औद्योगिक लेड एसिड बैटरीज है। ये बैटरियाँ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत विद्युतीय संचायक के रूप में वर्णित हैं और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम उपशीर्ष संख्या 8507.10 एवं 8507.20 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योगों के विचार

19. नई शिपर समीक्षा की शुरुआत के पश्चात प्राप्त घरेलू उद्योगों के विचार, एवं प्रकटन विवरण के समय तक की गयी टिप्पणी का पैरा 21-31 में सारांश में दिया गया है और पुनः प्रस्तुत किया गया है।

20. न्यू शिपर समीक्षा की मांग करने वाली कंपनियाँ जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, अलग-अलग देशों की अलग-अलग विधिक सत्ताएं हैं और दोनों (देशों) में उनके अपने-अपने सामान्य मूल्य हैं। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने मूल जांच अवधि के दौरान किसी भी माल का निर्यात नहीं किया है। यहां तक कि उत्पादक ने मौजूदा जांच अवधि के दौरान भी किसी माल का निर्यात नहीं किया है। निर्यातक एक ऐसे अलग देश, जिसका अपना सामान्य मूल्य है और जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, की एक पृथक विधिक सत्ता होने के कारण नई शिपर द्वारा किए गए निर्यात को उत्पादक का निर्यात होने का दावा नहीं किया जा सकता है।

21. सिंगापुर के निर्यातक (व्यापारी) और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य अलग-अलग हैं क्योंकि दोनों अलग-2 देशों में हैं और दोनों देशों का अपना सामान्य मूल्य है। वास्तव में, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग के विरुद्ध पाटनरोधी जांच के कारण सिंगापुर के निर्यातक पर पहले से ही अवशिष्ट शुल्क लगाया जा रहा है।

22. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने वाले व्यापारी ने खुद को न तो मौजूदा याचिका में शामिल किया है न ही यह प्रमाणित किया है कि उसने पिछली जांच अवधि के दौरान माल का निर्यात किया है और न ही यह प्रमाणित किया है कि पूर्ववर्ती जांच अवधि में निर्यात करने वाले उत्पादक/निर्यातक से संबंधित है। वास्तव में, व्यापारी ने पिछली जांच अवधि में माल का निर्यात किया था और वह एक ऐसे उत्पादक से संबंधित है जिसने पिछली जांच अवधि में माल निर्यात किया था।

23. नियम 22 के अंतर्गत उत्पादक और निर्यातक शब्दों का प्रयोग एक ही साथ किया गया है। अतः यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि उत्पादक और निर्यातक शब्द का अर्थ समान है। नियम में साफ तौर पर दोनों

शब्दों के बीच फर्क किया गया है। सी एफ एल से संबंधित पाटनरोधी जांच में यह पुनः सिद्ध हो गया है जिसमें याचिकाकर्ता के स्वयं यह स्वीकार करने के बावजूद कि संबद्ध वस्तु का हांगकांग में उत्पादन नहीं होता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हांगकांग से हुए निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है। साथ ही साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी ने व्यापारियों के संबंध में अलग-अलग पाटनरोधी शुल्क एवं पाटन मार्जिन की सिफारिश की है। ऐसा मामला होने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारी और उत्पादक एक समान मानने का दावा नहीं किया जा सकता है।

24. यह मानते हुए कि उत्पादक और निर्यातक शब्द का समान अर्थ है और निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात को उत्पादक द्वारा किया गया निर्यात माना जाना चाहिए तो भी उत्पादक नए शिपर के दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में उत्पादक इस बारे में संतुष्ट नहीं कर सकता कि पिछली जाँच अवधि में माल का निर्यात करने वाली किसी उत्पादक/निर्यातक से उसका संबंध नहीं था।

25. यद्यपि याचिका उत्पादक द्वारा दाखिल की गयी थी तथापि प्रश्नावली का उत्तर एक भिन्न देश के व्यापारी और याचिकाकर्ता उत्पादक द्वारा दाखिल किया गया है। इस प्रकार किसी आवेदन के बिना व्यापारी ने प्रश्नावली के उत्तर के चरण पर स्वयं को प्रस्तुत किया है और वह भी किसी पत्र प्राधिकार और प्रमाणन के बिना वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि व्यापारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना पर विचार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

26. ऐसा मामला होने के कारण दोनों याचिकाकर्ता निर्यातकों के संबंध में की गयी समस्त जांच निम्न आधारों पर समाप्त करनी अपेक्षित है।

(क) याचिकाकर्ता, उत्पादक नियम 22 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते।

(ख) याचिकाकर्ता उत्पादक वर्तमान जांच अवधि में किए गए निर्यात के संबंध में अपना निर्यात मूल्य रखने का दावा नहीं कर सकते।

(ग) जब निर्यात के देश का अपना सामान्य मूल्य हो तो मूल देश के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(घ) माल निर्यात करने वाली कंपनी ने कोई याचिका दाखिल नहीं की है और न ही उसमें नियमान्तर्गत यथापेक्षित आवश्यक वैधानिक घोषणाएं प्रस्तुत की हैं।

27. निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए काफी समय लिया है।

28. मौजूदा जांच के लिए विचारित अवधि भविष्यलक्षित है जबकि पहले प्रारंभ किए गए अनेक मामलों में नियम 23 के अंतर्गत समीक्षा एवं नियम 5 के अंतर्गत नवीन जाँच के लिए पिछली जांच अवधि के रूप में जांच अवधि निर्धारित की गयी थी। भारतीय उत्पादकों द्वारा भविष्य लक्ष्यी जांच अवधि का औचित्य समझ में नहीं आता खासकर तब जबकि भविष्य में होने वाले ऐसे निर्यात के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए भावी जांच अवधि निर्धारित की जाती है। भविष्य लक्ष्यी जांच अवधि के मामले में इस बात की काफी अधिक संभावना है कि कम पाटन मार्जिन प्राप्त करने के लिए निर्यातक माल का निर्यात संतुलित मूल्य पर कर सकता है और निर्यात की गयी मात्रा भी प्रतिनिधिक नहीं हो सकती। अतः प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यात की ऐसी कुछ मात्रा होनी चाहिए जिसे इस तरह के निर्यात संबंधी पाटन मार्जिन निर्धारित करने से पहले निर्यात कर चुका हो और उचित एवं न्याय संगत तरीके से यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि निर्यात मूल्य प्रतिनिधिक है। निर्यात मूल्य स्वीकार करने से पहले (क) क्षतिपूरक प्रबंधों की

ऐसोसिएशन/मौजूदगी (ख) उत्पादक का पुनर्विक्रय मूल्य (ग) वह मूल्य जिस पर आयातक ने अन्य स्रोतों से समान वस्तु खरीदी (घ) विक्रेता एवं क्रेता के बीच किसी तरह के वैधानिक अथवा संविदात्मक संबंध जैसे तथ्यों की जांच किए जाने की जरूरत है।

29. निर्यातक को सूचना एवं साक्ष्य के आधार पर इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि वे बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार (एम ई टी) की पूर्ति करते हैं और घरेलू उद्योग को इस संबंध में अपने दावे को औचित्य पूर्ण ठहराने एवं उसके समर्थन में कोई भी दस्तावेज/सूचना/साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ था। सार्वजनिक सुनवाई के समय भारतीय उत्पादकों के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी कि निर्यातक ने इस बारे में कुछ गोपनीय दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया अगोपनीय अंश अत्यंत अपर्याप्त है।

30. किसी न्यू शिपर समीक्षा में यह शर्त होती है कि निर्यातक को ऐसे किसी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित नहीं होना चाहिए जिसने माल का पाटन किया है। इस बात को स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि सी एस बी ने विगत में और प्राधिकारी द्वारा चुनी गयी जांच अवधि में भी बैटरियों का निर्यात किया है एवं भारत में उनका पाटन किया है। सी एस बी ने बड़ी मात्रा में बैटरियों की भारत को बिक्री की है। इसने विभेदकारी कीमतों का सहारा लिया है और अन्ततः अपनी कीमतें 1.24 अमरीकी डालर/किग्रा० (2.7 किग्रा० की प्रत्येक बैटरी के लिए 3.55 अमरीकी डालर) से भी कम कर दी हैं। इससे संबद्ध प्रत्यक्ष लागतों की वसूली भी नहीं होती है। यह देखा जा सकता है कि या तो (क) घरेलू/तीसरे देश के बाजार में निर्यातक की बिक्री कीमत अधिक है; अथवा (ख) निर्यातक को घरेलू/तीसरे देश के बाजार में वित्तीय हानि हुई है। दोनों स्थितियों में पाटन मार्जिन धनात्मक और महत्वपूर्ण है।

31. घरेलू उद्योग ने एक बार फिर अगोपनीय तरीके से उपयुक्त रूप में सूचना देने में याचिकाकर्ता की असफलता के आधार पर जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण गैर बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर करना अपेक्षित है और यह भी कहा कि यद्यपि वे बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के पात्र हैं तथापि सामान्य मूल्य का निर्धारण जवाब देने वाले अन्य जांचाधीन याचिककर्ताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

निर्यातकों के विचार

32. न्यू शिपर समीक्षा के आरम्भ होने के पश्चात प्रकटन विवरण से संबंधित टिप्पणियों तक प्राप्त घरेलू उद्योगके विचारों का संक्षेपण किया गया है और उन्हें पैरा 33 से 43 में उद्धृत किया गया है।

33. मै० सी एस बी बैटरी गुआंगझो कंपनी लि०, चीन जनवादी गणराज्य से इस विषय पर प्रश्नावली के बारे में अपने उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया था। उनके जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने जांच की अवधि से पूर्व भारत को कोई निर्यात नहीं किए हैं। भारतीय उत्पादकों के पास ऐसी आपत्ति उठाने के लिए कोई अधिकारिता नहीं है क्योंकि निर्यातक द्वारा किए गए सभी अनुरोध प्राधिकारी से उपयुक्त समय सीमा बढ़ाने की मांग करने के पश्चात किए गए थे। यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारतीय उत्पादकों को कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता क्योंकि अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने से केवल निर्यातक के हित प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय उत्पादकों के प्रतिनिधि ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि यह वृद्धि सार्स समस्या को ध्यान में रखते हुए की गयी थी, जिसने लोगों को चीन जनवादी गणराज्य के हिस्सों में यात्रा करने से रोका था।

34. भारतीय उत्पादकों के प्रतिनिधि ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आरम्भ किए गए पहले के मामलों पर ध्यान दिया है और पाया कि पिछली अवधि के लिए जांच की अवधि पहले ही निर्धारित की जाती थी। भारतीय उत्पादकों ने ऐसे एक भी मामले का उल्लेख नहीं किया है जहाँ जांच की

अवधि केवल पिछली अवधि के लिए है। इसके मद्देनजर, यह तर्क पूर्णतः अप्रमाणित है और इस पर उपयुक्त रूप से टिप्पणी नहीं की जा सकती। भारतीय उत्पादकों के तथाकथित प्रतिनिधि ने प्राधिकारी का ध्यान कानून के किसी प्रावधान अथवा डब्ल्यू टी ओ प्रावधान की ओर भी आकर्षित नहीं किया है, जो न्यू शिपर समीक्षा के मामले में केवल पिछली अवधि पर ही विचार अथवा अधिदेश करता है। नियम 5 और नियम 23 का संदर्भ अप्रासंगिक है क्योंकि ये नियम एक नई जांच अथवा एक मध्यावधि समीक्षा पर लागू होते हैं। यह समझा जा सकता है कि न्यू शिपर समीक्षा उस निर्यातक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य से की जाती है, जो डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 9(5) अथवा पाटनरोधी नियमों के नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। वास्तव में, इस पद्धति का अमरीका, ई सी, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और ब्राजील सहित काफी देशों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। भारतीय उत्पादकों द्वारा व्यक्त की गयी आशंकाओं और अटकलों का ऐसी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो पूर्णतः कानूनों के अनुसार हो। भारतीय उत्पादकों द्वारा दिए गए सुझाव पूरी तरह पाटनरोधी नियमों से असंबद्ध हैं। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी उसी अधिनियम का एक अंग होने के कारण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बाध्य हैं और उन्हें मामले की जांच पाटनरोधी नियमों के नियम 22 के प्रावधानों के भीतर करनी होगी।

35. न्यू शिपर ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा किया था और अपने मामले के समर्थन में व्यापक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। कानून सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध है जबकि कच्चे माल की खरीद, लागतों, बिक्री कीमतों इत्यादि से संबंधित सूचना गोपनीय है। निर्यातकों ने यह भी उल्लेख किया है कि वे रिकार्ड में यह भी बताना चाहेंगे कि घरेलू उद्योग ने मूल जांच में सहयोगी निर्यातकों द्वारा किए गए लगातार अनुरोधों और अनुस्मारकों के बावजूद इस बारे में गोपनीयता का दावा किए बिना अन्य हितबद्ध पक्षों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से मना किया है। घरेलू उद्योग याचिका दायर करने की स्थिति के अपने दावे के समर्थन में घरेलू उत्पादन के ब्यौरे भी उपलब्ध कराने में असफल रहा है। भारतीय उत्पादक एक ही मामले में अलग-अलग मानदण्डों का अनुसरण करने का दावा नहीं कर सकते हैं।

36. इस दावे के संबंध में कि सी एस बी के लिए पाटन मार्जिन काफी पर्याप्त है, यह तर्क दिया गया है कि भारतीय उत्पादकों के प्रतिनिधि ने भारत को सी एस बी की निर्यात कीमत के बारे में कुछ काल्पनिक आंकड़े दिए हैं और अस्पष्ट रूप से उनके द्वारा पर्याप्त पाटन का आरोप लगाया गया है। इन सभी आधारहीन आरोपों को नकार दिया गया है। उनका यह दावा कि वे अपनी संबंधित प्रत्यक्ष लागतों से कम पर बिक्री कर रहे हैं, भी आधारहीन हैं जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

37. प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी करने की आवश्यकता के मुद्दे पर यह अनुरोध किया गया है कि यह पाटनरोधी कानूनों का एक निर्धारित सिद्धांत है कि आवेदक निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटनरोधी मार्जिन का निर्धारण करने के लिए जांच का दायरा प्रतिबंधित है। प्रारंभिक जांच परिणामों की मांग न केवल पाटनरोधी नियमों की स्कीम के विरुद्ध है बल्कि निर्यातकों के वैध दावे के विलंब के लिए भारतीय उत्पादकों द्वारा किया गया केवल एक प्रयास है।

38. जहाँ तक उठाए गए इस मुद्दे का संबंध है कि क्या एक निर्यातोन्मुखी एकक द्वारा अलग-अलग पाटन मार्जिन का दावा किया जा सकता है, यह अनुरोध किया गया है कि कोई कारण अथवा कानून का प्रावधान नहीं दिया गया है कि क्यों एक निर्यातोन्मुखी इकाई एक न्यू शिपर समीक्षा मामले में अलग-अलग पाटन मार्जिन का दावा खो देती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं कई मामलों में सहयोगी निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है वह भी यह ध्यान दिए बिना कि क्या वे निर्यात अभिमुख थे अथवा नहीं। अनेक भारतीय निर्यातक (ई ओ यू) ई सी और अन्य देशों में अलग-अलग पाटन मार्जिन प्राप्त करने में सफल रहे हैं। यह इस तथ्य के कारण सही है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण को बाधित करता हो।

39. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान एच एंड आर जॉनसन बनाम वित्त मंत्रालय और अन्य के मामले में माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश की ओर भी आकर्षित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय मामले के तथ्यों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है और इस मामले का निर्णय अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए इस न्यू शिपर समीक्षा पर लागू होगा।

40. न्यू शिपर के उन निर्यातकों के साथ संबंधों के मुद्दे पर, जिन पर पूर्ववर्ती जांचों में पाटनरोधी शुल्क लगता रहा है, निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि न्यू शिपर को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि क्या वह विवादास्पद निर्यातक देश में किसी निर्यातक/उत्पादक से संबंधित है। इस संबंध में निर्यातक के प्रतिनिधि ने यूरोपीय आयोग के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है।

41. 18 मार्च, 2002 के परिषद विनियमन (ई सी) सं. 496/2002 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि 'इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार कंपनी संतोषजनक ढंग से यह प्रदर्शित करने में सफल थी कि इसके संबंधित उत्पाद के संबंध में लागू पाटनरोधी उपायों के अधीन किसी भारतीय निर्यातकर्ता उत्पादक के साथ किसी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।' 27 नवम्बर, 2000 का मूल परिषद विनियमन सं. 2604/2000 भारत सहित विभिन्न देशों के विरुद्ध था लेकिन संबंध के मुद्दे की जांच केवल विवादास्पद निर्यातक देश के संदर्भ में की गयी है।

42. 20 नवम्बर, 2000 के परिषद विनियमन सं. 2570/2000 में यह उल्लेख किया गया है कि 'इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार कंपनी संतोषजनक ढंग से यह प्रदर्शित करने में सफल थी कि इसके उत्पाद के संबंध में लागू पाटनरोधी उपायों के अधीन किसी चीनी निर्यातकर्ता उत्पादक के साथ किसी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।' 16 फरवरी, 1998 के मूल परिषद विनियमन सं. 393/98 में यह उल्लेख है कि मूल जांच चीन सहित विभिन्न देशों के विरुद्ध थी किन्तु संबंध के मुद्दे की जांच केवल विवादास्पद निर्यातक देश के संदर्भ में की गयी थी।

43. निर्यातक ने यूरोपीय संघ के कुछ और निष्कर्षों का उल्लेख किया है। जिनमें यह कहा गया है कि न्यू शिपर जाँच तभी शुरू की जाए जबकि कंपनी संतोषजनक ढंग से यह प्रदर्शित किया हो कि संबंधित उत्पाद के बारे में लागू पाटनरोधी उपायों के अधीन न्यू शिपर से संबंधित देश में किसी निर्यातक/उत्पादक के साथ उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था। आगे यह बताया गया है कि ई सी ने न्यू शिपर से संबंध की जांच केवल जाँचाधीन देश के निर्यातक या उत्पादक के साथ की है और न कि मूल या किसी अन्य पाटनरोधी जाँच में शामिल संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों के साथ।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

44. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किये गए पर्याप्त आधार पर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए समय सीमा को बढ़ाया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने बढ़ाए गए समय के भीतर सभी उत्तरों को प्रस्तुत कर दिया था। घरेलू उद्योग का यह तर्क कि उत्तर देने में निर्यातक ने अनावश्यक देरी की है, सही नहीं है।

45. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत की, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

* नियम 22 : (1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी जाँचाधीन निर्यातक देश में किसी निर्यातक या उत्पादक जिन्होंने जाँच अवधि के दौरान भारत को उक्त उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए पाटन के अलग-अलग मार्जिनों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ समय-समय पर समीक्षा करेंगे बशर्ते कि ये निर्यातक या उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि वे निर्यातक देश में उन निर्यातकों या उत्पादकों से संबद्ध नहीं हैं जिनके इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

(2) केन्द्र सरकार इस अधिनियम की धारा 9(क) की उप-धारा (1) के अंतर्गत इस नियम के उप-नियम (1) में यथा उल्लिखित समीक्षा अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार अनंतिम निर्धारण कर सकती है और वह उक्त आयातक से गारंटी की माँग कर सकती है यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी सिफारिश करते हैं और यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप उन उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता है, तो वे ऐसे मामलों में समीक्षा शुरू होने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क लगा सकते हैं।

46. नियम 22 में उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना के प्रयोजनार्थ न्यू शिपर जाँच आरम्भ की जा सकती है। जाँचाधीन देश के किसी निर्यातक के संबंध में अलग से पाटन मार्जिन का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब दोनों शर्तें पूरी होती हों। ये इस प्रकार हैं (क) कि निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है और (ख) निर्यातक या उत्पादक यह दर्शाता है कि वे निर्यातक देश में ऐसे किसी

निर्यातक या उत्पादक से संबद्ध नहीं है जिनके उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह पाते हैं कि निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। जाँचाधीन निर्यातक देश से किसी निर्यातक के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन तभी निर्धारित किया जा सकता है जब उपरोक्त शर्तें पूरी होती हों। वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्यातक की घोषणाओं के आधार पर न्यू शिपर समीक्षा शुरू की थी।

47. जहाँ तक भविष्यलक्षी जाँच अवधि पर विचार करने की वैधता का संबंध है, नियम 22(2) के प्रथम परन्तुक का संदर्भ देना संगत होगा। इस परन्तुक के तहत केन्द्र सरकार को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश करने पर किसी नए निर्यातक के संदर्भ में आयातों के अनंतिम रूप से मूल्यांकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि नियम 22 में या पाटनरोधी नियमावली के किसी अन्य भाग में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें यह सुझाव दिया गया हो कि नियम 22 के अंतर्गत यथा परिकल्पित जाँच अवधि भविष्यलक्षी अवधि नहीं हो सकती है। प्राधिकारी की जानकारी में यह बात भी लाई गई है कि अन्य न्याय व्यवस्था के कानून एवं व्यवहार में भी इस विचार का समर्थन किया गया है कि न्यू शिपर के मामले में जाँच की भविष्यलक्षी अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उपरोक्त पर विचार करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना से आगे जाँच अवधि का निर्धारण करने में वह गलत नहीं हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियम 5 और नियम 23 के संदर्भ में घरेलू उद्योग के तर्क असंगत हैं। क्योंकि वे नियम नई जाँच या मध्यावधि समीक्षा पर लागू होते हैं।

48. घरेलू उद्योग ने यह आशंका भी व्यक्त की है कि भविष्यलक्षी जाँच अवधि निर्धारित करने से निर्यातक कीमतों में हेराफेरी करने की स्थिति में होगा जिसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन कम हो जाएगा। प्राधिकारी के लिए इस परिकल्पना को स्वीकार करना मुश्किल है जो अनुमानों और आशंकाओं पर आधारित है। प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच परिणामों के निर्धारणार्थ निर्यातक की लागतों, कीमतों, बिक्री की पद्धति बीजकों आदि की ब्योरेवार जाँच की है; जिनका सत्यापन मौके पर जाँच के दौरान किया गया था।

49. इसके अलावा प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निहित न्यू शिपर संबंधी समीक्षा की जाँच की है और यह नोट करते हैं कि करार के अनुच्छेद 9.5 के अंतर्गत संबंध का परीक्षण निर्यातक देश में निर्यातकों और उत्पादकों के बीच किया जाना चाहिए और न कि उन भिन्न-भिन्न देशों के निर्यातकों और उत्पादकों के बीच जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। यह भी पाया गया है कि ई सी न्यू शीपर जाँच में उसी देश के निर्यातकों और उत्पादकों के बीच संबंध की जाँच करता है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि सी एस बी चीन को उसके सी एस बी सिंगापुर से संबंधित होने के आधार पर न्यू शिपर समीक्षा से बाहर रखना उचित नहीं होगा।

50. जहाँ तक मै0 एच एण्ड आर जॉनसन बनाम वित्त मंत्रालय एवं अन्य के मामले में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, माननीय न्यायालय ने निर्यातक, यदि वे उसी देश का नहीं हो, की घोषणा के बारे में नियम 22 के अंतर्गत अलग-अलग मापदंडों के आधार पर दिशानिर्देश दिए हैं। वर्तमान मामले में निर्यातक, जिसपर प्रत्यक्ष रूप से पाटनरोधी शुल्क लागू है, के साथ न्यू

शिपर के संबंध का मुद्दा उठाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है।

51. (i) प्राधिकारी ने जाँच की प्रक्रिया के दौरान और मौके पर जाँच के दौरान आगे सत्यापित और समन्वित निर्यातक की सूचना/आँकड़ों की बारीकी से जाँच एवं विश्लेषण किया है।

(ii) यह भी तर्क दिया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रखी गई महत्वपूर्ण सूचना के कारण विरोधी हितबद्ध पक्षकार सूचना को चुनौती देने और प्राधिकारी के समक्ष सार्थक अनुरोध करने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। तथापि विरोधी हितबद्ध पक्षकार को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में गोपनीयता से संबंधित उपबंधों के अनुसार कार्य किया गया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में हितबद्ध पक्षकार द्वारा नियम में दी गई शर्त के अधीन गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय सारांश सार्वजनिक फाइल में रखा जाता है जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाता है। इस मामले में गोपनीय अनुरोधों के अगोपनीय सारांश को हितबद्ध पक्षकारों के लिए सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध रखा गया था।

घ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना की पद्धति का मूल्यांकन

घरेलू उद्योग के विचार

52. वर्तमान जांच को एन एम ई संबंधी संशोधित नियमावली के अनुसार करना अपेक्षित है। निर्यातक को सूचना/साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध करना होगा कि वे बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी योग्यता को पूरा करते हैं। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय अंश निर्यातक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के सार तत्व को समझने की दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त और अधूरा है। उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि ई सी के अनेक निर्णय जिनमें यदि नियमों के अंतर्गत उल्लिखित कुछेक शर्तें पूरी नहीं की गई हों तो भी इस आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी दावे को अस्वीकार किया गया है।

निर्यातक के विचार

53. इस मामले में निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा किया है और उसके समर्थन में विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। कानून सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं जबकि कच्ची सामग्रियों, लागतों, बिक्री कीमतों आदि से संबंधित सूचना गोपनीय प्रकृति की होती है। उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किए जाने के लिए अपने दावे के लिए और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 से 6 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रत्येक मापदंड संबंधी ब्योरे प्रस्तुत किए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

54. वर्तमान मामले में, चीन की एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाँच करने का प्रस्ताव है। मूल जाँच में याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि यूरोपीय आयोग और अमरीका ने पिछले तीन वर्षों में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। इसलिए, चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण दिनांक 04.01.2002 की अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 में यथा उल्लिखित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

55. जैसा कि निर्यातक तथा चीन के दूतावास को सूचित किया गया है, प्राधिकारी ने यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 एवं 8 के आलोक में सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रस्ताव किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि:-

'गैर-बाजार देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहाँ यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा।'

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त नियमावली (यथासंशोधित) के अनुबंध-1 के पैरा-8 में व्यवस्था है कि:-

'8. (1) 'गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश' शब्द का अर्थ है कि कोई देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों को लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियाँ उप पैराग्राफ-3 में निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।'

(2) यह कहना परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश है,

तथापि गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के उप पैरा 3 में उल्लिखितानुसार आवश्यक जानकारी/साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं जिसके आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी, निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सके कि क्या:

(क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं;

- (ख) ऐसे फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर बाजार अर्थ व्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के ह्रास, अन्य राइट ऑफ, वस्तु विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;
- (ग) ऐसी फर्म दिवाला तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; तथा
- (घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसे अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

57. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंधित क्रिया-कलापों का प्रारंभ प्राधिकारी इस परिकल्पना के साथ करते हैं कि देश की सभी कम्पनियां सरकारी नियंत्रणाधीन हैं और इसलिए उन्हें एक एकल पाटनरोधी दर प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि कोई निर्यातक सरकारी नियंत्रण की अनुपस्थिति में कानूनी एवं तथ्यात्मक दोनों ही रूपों में अपनी बिक्रियां - घरेलू एवं निर्यात दोनों में ही सकारात्मक प्रदर्शन करने में समर्थ न हों। इस समीक्षा में न्यू शिपर मै0 सीएसबी चीन जन0 गण0 ने एक कम्पनी विशिष्ट निर्धारण का अनुरोध किया है।

58. यह ज्ञात करने के लिए कि क्या एक कम्पनी पृथक, कम्पनी विशिष्ट दर प्रदान किए जाने हेतु अपने निर्यात क्रियाकलापों में सरकारी नियंत्रण से पर्याप्त रूप से स्वतंत्र हैं; प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित जांच के तहत एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में निर्यात निकाय का परीक्षण किया था। प्राधिकारी की व्यक्तिगत व्यवहार जांच बड़े आर्थिक/बॉर्डर टाइप नियंत्रणों जैसे निर्यात लाइसेंस कोटा तथा न्यूनतम निर्यात कीमत से संबद्ध नहीं है विशेषकर यदि ये नियंत्रण पाटन को रोकने के लिए लागू किए गए हों। इसके बजाय प्राधिकारी की जांच का फोकस, निवेश, कीमत निर्धारण तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया पर व्यक्तिगत कम्पनी विशिष्ट स्तर के नियंत्रण पर होता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह उत्पादक/निर्यातक सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है अथवा नहीं, विश्लेषण किया है।

59. प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी विशिष्ट कम्पनी को प्रचलित बाजार अर्थव्यवस्था के कारण एक पृथक दर प्रदान की जा सकती है; निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया;

- किसी विशिष्ट निर्यातक के व्यावसायिक तथा निर्यात लाइसेंसों से संबंधित नियामक शर्तों का अभाव।
- कम्पनियों पर नियंत्रण को विकेन्द्रीकृत करने वाला कोई कानूनी अधिनियम, तथा
- सरकार द्वारा कम्पनियों पर नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण करने हेतु अन्य औपचारिक उपाय

60. सीएसबी चीन ने राज्य हस्तक्षेप तथा नियंत्रण अर्थात् कम्पनी कानून, श्रम कानून, संयुक्त उद्यम कानून तथा लेखा संबंधी नियम अथवा कानून की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने ऐसे पीआरसी कानूनों का विश्लेषण किया और कम्पनी के कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लिए जाने के बारे में कम्पनी पर सरकारी नियंत्रण को अनुपस्थित पाया। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि क्या उत्तरप्रदाता अपनी बिक्री तथा प्राप्ति गतिविधियों में सरकारी नियंत्रण के अधीन है,

- (i) क्या निर्यात कीमत का निर्धारण किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है अथवा उसका निर्धारण सरकारी प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन है,
- (ii) क्या उत्तरप्रदाता के पास संविदाओं तथा अन्य करारों पर विचार-विमर्श करने तथा उन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है,
- (iii) क्या उत्तरप्रदाता अपने प्रबंधन का चयन करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए सरकार से स्वतंत्र है,
- (iv) अतः, क्या उत्तरप्रदाता अपनी निर्यात बिक्रियों की प्राप्ति को अपने अधिकार में रखता है और लाभ के वितरण अथवा हानि के वित्तपोषण के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है,
- (v) प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए कम्पनी यह प्रदर्शित करने में सक्षम रही थी कि उत्पादन, विपणन तथा कीमत-निर्धारण के बारे में फैक्टरी का प्रबंधन एवं नियंत्रण कम्पनी के प्रबंधन के हाथों में था, जो राज्य हस्तक्षेप से पूरी तरह से स्वतंत्र था।

61. न्यू शिपर के अनुसार वह विदेशी पूँजी इंटरप्राइजेज संबंधी चीन जनवादी गणराज्य के कानून के अंतर्गत एक लिमिटेड कम्पनी है और प्रारंभ से उसके कानूनी रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि निर्यात/घरेलू कीमत के निर्धारण में सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। प्रबंधन बिक्री संविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए स्वतंत्र है। प्राधिकारी/प्रबंधन अपने प्रबंधन का चयन करने के बारे में किसी सरकारी प्राधिकरण को अधिसूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। कम्पनी सरकार से अनुमति लिए बिना अथवा उसे सूचित किए बिना राजस्व के उपयोग के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों के विश्लेषण से सरकारी नियंत्रण की उपस्थिति प्रकट नहीं होती है।

62. सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए आँकड़ों का सत्यापन किया गया था और उनका मिलान उनके लेखों से और राज्य हस्तक्षेप की उपस्थिति के संबंध में किया गया था। प्राधिकारी यह अवलोकन करते हैं कि जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -1 के पैराग्राफ 8(3) (क) में परिकल्पित है, निवेशों, बिक्री कीमतों/लागतों आदि के संबंध में निर्णय लिए जाने में चीन सरकार का कोई प्रभाव नहीं है।

63. कीमत निर्धारण तथा कच्ची सामग्री की लागत की जाँच के आधार पर प्राधिकारी ने यह पाया है कि जैसा कि कम्पनी के लेखा बही, संबंधित मदों आदि से सत्यापित किया गया, किसी उत्पादन लागत तथा कम्पनी की वित्तीय स्थिति से कोई विरूपण प्रदर्शित नहीं होता है।

64. दिवालिया तथा संपत्ति कानूनों पर भी वार्ता की गई थी और यह पाया गया था कि चीन में कम्पनियाँ संपत्ति के अधिग्रहण के लिए स्वतंत्र हैं तथापि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षेत्र कानून उद्योगों पर विनियमित होता है। दिवालिया कानून किसी फर्म पर तब लागू होता है जब कम्पनी दिवालिया हो जाती है और बकाया राशि के भुगतान संबंधी विवरण दिवालिया कानून के अंतर्गत उल्लिखित कानून द्वारा शासित होते हैं।
65. उनके लेखा बही तथा निर्यात सौदों से विनिमय दर रूपान्तरों का भी सत्यापन किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी रूपान्तर वर्तमान दर किए गए हैं जो बिना अधिक घट-बढ़ के प्रायः स्थिर रही है।
66. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कम्पनी चीन में अथवा विश्व के दूसरे हिस्सों से कच्ची तथा अर्ध-परिष्कृत सामग्री, ईंधन तथा अन्य सामग्रियाँ खरीदने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान में कम्पनी मुख्य कच्ची सामग्री अर्थात् लेड ऑस्ट्रेलिया, ताइवान तथा कोरिया से खरीद रही है जबकि बाकी सामग्री चीन में ही खरीदी जाती है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि उन्होंने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न दरों पर लेड खरीदा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा गया है।
67. विद्युत की प्राप्ति स्थानीय प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली विद्युत कम्पनी से की जाती है। गैस की आपूर्ति भी एक निजी कम्पनी द्वारा की जाती है और औसत खरीद दर 10.3716 आरएमबी प्रति क्यूबिक मीटर है।
68. रोजगार संबंधी सभी निर्णय कम्पनी द्वारा लिए जाते हैं और कर्मचारियों की नियुक्ति समाचार पत्र के विज्ञापनों, निजी रोजगार एजेंसियों आदि के माध्यम से की जाती है। कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति के संबंध में कम्पनी को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है और कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को दिए जाने वाले औसत वेतन का भुगतान निष्पादन प्रोत्साहन सहित किया जाता है। चीन सरकार द्वारा आवास, चिकित्सा सुविधा आदि जैसे लाभ नहीं दिए जाते हैं किन्तु कम्पनी द्वारा सभी को आवास उपलब्ध कराया जाता है और लेखा बही में इसकी लागत को व्यय के रूप में दर्शाया गया है।
69. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है। कीमत/मात्रा में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ऐसे सभी निर्णय विशुद्ध वाणिज्यिक आधार पर लिए जाते हैं। घरेलू बिक्री अथवा निर्यात के लिए कोई कीमत सूची नहीं है क्योंकि कीमत में उपभोक्ता के आधार पर अंतर होता है और इसका निर्धारण बाजार में माँग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर होता है।
70. कम्पनी की बहियों तथा रिकॉर्डों को मंडारिन में रखा गया है और आँकड़े रेनमिन (आरएमबी) में निर्दिष्ट किए गए हैं। विदेशी संयुक्त उद्यम पर लागू होने वाले लेखा संबंधी नियम तथा सिद्धांत कानून के अनुरूप हैं।
71. कम्पनी की सभी परिसम्पत्तियाँ मुक्त बाजार से विशुद्ध वाणिज्यिक आधार पर प्राप्त की गई हैं। कोई भी परिसम्पत्ति राज्य द्वारा अथवा किसी तीसरी स्वतंत्र कम्पनी द्वारा अथवा वाणिज्यिक सिद्धांतों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। भू-संपत्ति के अतिरिक्त

अन्य सभी परिसम्पत्तियाँ कम्पनी के स्वामित्व में है जबकि भू-संपत्ति को 15 वर्षों के दीर्घावधि पट्टे पर लिया गया है। कम्पनी का पूरा वित्तपोषण शेयर धारकों द्वारा किया जाता है। ऋणों अथवा विद्युत आपूर्ति, जिसका लाभ कम्पनी को उपलब्ध है, के लिए कोई सब्सिडी योजना नहीं है।

72. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों के संबंध में कम्पनी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निविष्टियों की खरीद निर्यात बिक्री की प्राप्ति का परिवर्तन तथा मुनाफों का स्वदेश-प्रेषण एकल विनिमय दर पर किया गया है। शेयर धारकों को मुनाफे का वितरण लेखांकन विनियमों के तहत किया जाता है तथा निवेश की गई पूंजी के लिए मुनाफे के वितरण/स्वदेश प्रेषण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

73. प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर निर्यातक द्वारा उपर्युक्त पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्दे के संबंध में पाटनरोधी सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 28/2001 दिनांक 31 मई, 2001 एवं सं. 1/2002 दिनांक 4 जनवरी, 2002 के तहत साक्ष्य सहित उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत बाजारी शक्तियों के अनुसार उपलब्ध कराई गई है, प्राधिकारी इस एकल निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था में कार्यरत मानने पर विचार कर रहे हैं। एमओएफसीओएम (चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय) के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह बताया गया था कि राज्य का इसके प्रचालन तथा प्रबंधन के मामले में कोई नियंत्रण नहीं है जिसे वास्तव में निर्यातक के पास उपलब्ध अभिलेखों से सत्यापित किया गया था। कम्पनी प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप यह प्रदर्शित कर सकी थी कि उत्पादन, विपणन तथा कीमत निर्धारण के संबंध में फैक्टरी का प्रबंधन तथा नियंत्रण, प्रबंधन के अधीन था जो कि राज्य के हस्तक्षेप से काफी हद तक स्वतंत्र थे। उपर्युक्त जांच के आलोक में नए शिपर को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करने तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-1 से 6 के अनुसार सामान्य मूल्य को निर्धारित करने पर विचार किया गया था।

74. 9क(1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है कि:-

- (i) सामान्य तौर पर होने वाले व्यापार में उस समान प्रकार के वस्तु के लिये तुलनात्मक मूल्य जो उपखंड (6) के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए अभिप्रेत हो; और
- (ii) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य तौर पर होने वाले व्यापार में समान प्रकार की वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती हो अथवा जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में किसी विशेष प्रकार की बाजार स्थिति अथवा बिक्री की कम मात्रा के कारण इस प्रकार की बिक्री से एक उचित तुलना नहीं हो पाती तो सामान्य मूल्य निम्न में से कोई एक होगा:-

(क) उपनियम 6 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यथानिर्धारित समान प्रकार की उस वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधित्व मूल्य जब वह वस्तु निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उचित तीसरे देश से निर्यातित होती हो; अथवा

(ख) प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और उपनियम-6 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यथानिर्धारित लाभ के लिये उचित मार्जिन के साथ मूल के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

सामान्य मूल्य

75 प्राधिकारी ने मै0 सीएसबी गौंझाऊ बैटरी कं0 लिमि. को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (1) (ग) के तहत सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी। प्रश्नावली के जवाब में मै0 सीएसबी गौंझाऊ बैटरी कं0 लि0 ने निर्यातक प्रश्नावली में सूचनाएं प्रस्तुत की थीं। चूंकि कम्पनी घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री नहीं करती है इसलिए सामान्य मूल्य का आकलन या तो उचित तीसरे देश को किए गए निर्यात के आधार पर अथवा उत्पादन की लागत में तर्कसंगत आय को जोड़कर करना होता है। चूंकि तीसरे देशों को किए गए निर्यात घाटे के सौदे थे इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में इनकी अनदेखी की तथा उत्पादन की लागत में तर्कसंगत आय जोड़ने की विधि का उपयोग किया। कम्पनी ने भारत को बेची गई बैटरियों के विभिन्न माडलों के उत्पादन की लागत के ब्यौरे उपलब्ध करवाए हैं - तथा यही निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य के आकलन के आधार है। निर्यातक ने परिशिष्ट-8,9, तथा 10 के अनुसार विभिन्न प्रकार की औद्योगिक बैटरियों के उत्पादन की लागत भी प्रस्तुत की है। इसके अलावा, सत्यापन के दौरान निर्यातक को परिशिष्ट-8,9, तथा 10 में दर्शाई गई उत्पादन की लागत को स्पष्ट करने तथा इसे जांच अवधि के लिए खाता बही/लाभ तथा हानि खाते से मिलान करने के लिए कहा गया था। तथापि, निर्यातक द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि इन परिशिष्टों में दर्शाई गई उत्पादन की लागत वास्तविक आधार पर ली गई हैं।

76. निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान उत्पादित विभिन्न माडलों की लैड एसिड बैटरियों के उत्पादन की लागत के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। जांच अवधि के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि लेखों को भी मासिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। निर्यातक ने जांच अवधि के लिए उत्पादन की लागत का खाता बही/लाभ एवं हानि लेखों से मिलान उपलब्ध कराया था। यह पाया गया था कि लागत विवरण में प्रदर्शित तथा सत्यापन के दौरान आकलित उत्पादन की लागत में, लाभ एवं हानि लेखों के अनुसार लागत पर विचार करने पर इसमें 6.07% की सीमा तक व्ययों की कम प्रतिपूर्ति हुई है। जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत का आकलन करते समय इसका उचित ध्यान रखा गया है।

77. कम्पनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को औद्योगिक बैटरियों के तीन माडलों का निर्यात किया है। बैटरी वार प्रत्येक औद्योगिक लैड एसिड बैटरी का कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य ****, **** तथा **** अमरीकी डालर संदर्भित किया गया है।

निर्यात कीमत :

78. प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातक ने परिशिष्ट-2 में जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के बीजक-वार/माडल-वार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। निर्यातक ने इसके समर्थन में बीजकों की नमूना प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं। निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को अनुसूचित रहित औद्योगिक लैड एसिड बैटरियों का निर्यात किया है। निर्यातक द्वारा परिशिष्ट-4 में दावा किए गए अंतर्देशीय मालभाड़े, भण्डार हैंडलिंग, बीमा, पोत परिवहन प्रभारों इत्यादि के संबंध में समायोजन पर विधिवत सत्यापन के बाद विचार किया गया है और इनको भारत में कारखाना द्वार निर्यात कीमत पर पहुंचने की अनुमति दी गई है। उनके परिसर में मौके पर सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि मै0 सी एस बी, चीन जन0 गण0 द्वारा भारत को निर्यात सी वी आई लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन (सी वी आई), ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड्स के माध्यम से किया जाता है और सी वी आई ने माल को आगे सी एस बी बैटरी (सिंगापुर) पी टी आर लि0, (सी एस बी) को बेच दिया जिसने अन्ततोगत्वा माल का भारत को निर्यात कर दिया।

79. निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए सभी समायोजनों का पूर्ववर्ती ढंग से परिकलन किया गया है। इस संबंध में सी बी एस चीन से सी वी आई ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड्स और सी वी आई से सी बी एस सिंगापुर और अन्ततः सी बी एस सिंगापुर से भारतीय ग्राहकों से संबंधित बीजकों का सत्यापन किया गया था और इनको उनके द्वारा दावा किये गए समायोजनों के अनुकूल बनाया गया था। उनके समायोजनों से संबंधित ब्यौरों का सत्यापन किया गया था और उनको कम्पनी के पास उपलब्ध मूल रिकार्ड के अनुकूल बनाया गया था।

80. जांच अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा भारत को निर्यात की गई औद्योगिक लैड एसिड बैटरी की प्रति बैटरी बैटरी-वार निर्यात कीमत ****, ****, **** अमरीकी डालर बनती है।

पाटन मार्जिन :

81. चूँकि बैटरियों के मॉडलों और टाइपों की अनेक किस्में हैं, इसलिए गणना और तुलना के प्रयोजनार्थ इनमें समानता लाये जाने की जरूरत है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, विद्युत, शीशे की मात्रा और बैटरी के वजन में प्रत्यक्ष संबंध है जो मूल्य अथवा कीमत के रूप में भी प्रतिबिम्बित होता है। इसके अलावा शीशे की मात्रा और बैटरी के वजन तथा इसकी सम्बद्ध लागतों और कीमतों के बीच प्रत्यक्ष संबंध भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्राधिकारी तुलना तथा पाटन मार्जिन पर पहुँचने के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत को बैटरियों के वजन के रूप निर्दिष्ट करने पर विचार करते हैं। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत और जांच अवधि के दौरान सत्यापित किए गए तकनीकी ब्यौरों के आधार पर वजन पर विचार किया गया है। उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन 12.31% के रूप में निर्धारित किया गया है।

ड. समीक्षा संबंधी अंतिम जांच परिणाम

82. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :-

- (i) मै0 सी एस बी चीन जन0 गण0 से भारत को निर्यात की गई लैड एसिड बैटरियां जांच अवधि के दौरान इसके सामान्य मूल्य से कम है ।
- (ii) प्राधिकारी मै0 सी एस बी चीन जन0 गण0 के मूल की अथवा उसके द्वारा निर्यातित सीमा शुल्क कोड 8507 के अंतर्गत आने वाली लैड एसिड बैटरियों के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं0 9 में उल्लिखित राशि और मै0 सी एस बी चीन जन0 गण द्वारा निर्यातित/विनिर्मित प्रति कि० ग्राम लैड एसिड बैटरी के आयात के पहुँच मूल्य के बीच का अन्तर होगा और यह मै0 सी एस बी चीन जन0 गण0 के मूल की अथवा उसके द्वारा निर्यातित सीमाशुल्क कोड 8507 के अंतर्गत आने वाली लैड एसिड बैटरियों के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा पाटनरोधी नियमावली के पैरा 22(2) के अनुसार इस संबंध में जारी की जाने वाली प्रारंभिक जांच संबंधी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा ।

तालिका

क्र० सं०	उप-शीर्ष	माल का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	संदर्भ कीमत (अमरीकी डालर)	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	8507	लेड एसिड बैटरी		चीन जन० गण०	चीन जन० गण०	मै० सी एस बी बैटरी गुआंगडू कं० लि०	मै० सी एस बी बैटरी गुआंगडू कं० लि०	1.956	कि० ग्राम	अमरीकी डालर
2	8507	लेड एसिड बैटरी		चीन जन० गण०	सिंगापुर	मै० सी एस बी बैटरी गुआंगडू कं० लि०	मै० सी एस बी बैटरी गुआंगडू कं० लि०	1.956	कि० ग्राम	अमरीकी डालर
3	8507	लेड एसिड बैटरी		चीन जन० गण०	चीन जन० गण०	मै० सी एस बी बैटरी गुआंगडू कं० लि०	मै० सी एस बी सिंगापुर	1.956	कि० ग्राम	अमरीकी डालर
4	8507	लेड एसिड बैटरी		चीन जन० गण०	सिंगापुर	मै० सी एस बी बैटरी गुआंगडू कं० लि०	मै० सी एस बी बैटरी गुआंगडू कं० लि०	1.956	कि० ग्राम	अमरीकी डालर

(iii) इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क होंगे ।

(iv) इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NEW SHIPPER REVIEW NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2004

Subject:—New Shipper Review of Anti-Dumping duty imposed on Imports of Lead Acid Batteries requested by M/s. CSB Battery Guangzhou Co. Ltd, China PR—Final findings.

No. 14/26/2002-DGAD A. Procedure.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority initiated New Shipper Review of anti-dumping duty imposed on Lead Acid Batteries produced by M/s. CSB Battery Guangzhou Company Ltd., and exported by M/s. CSB Battery, Singapore prescribed under Rule 22 of the rules supra, vide notification No. 14/26/2002-DGAD, dated the 27th August 2002.

Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioners revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.

2. This New Shipper Review was initiated vide notification No. 14/26/2002-DGAD, dated the 27th August 2002 in the matter of import of Lead Acid Batteries falling under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from China PR where the Designated Authority vide its final findings published in the Gazette of India Extraordinary, Part I Section I, dated the 7th December 2001 had come to the conclusion that;

(i) Lead Acid Batteries exported to India from China PR, Korea RP, Japan and Bangladesh is below its normal value during the period of investigation;

(ii) The Indian industry has suffered material injury and is further being threatened with material injury;

(iii) The injury has been caused by the dumped imports from China PR, Korea RP, Japan and Bangladesh;

3. On the basis of the aforesaid findings of the Designated Authority, the Central Government had imposed anti dumping duty vide notification No. 1/2002—Customs dated the 2nd January 2002 published in the Gazette of India.

4. As stated above M/s. CSB Battery Guangzhou Company Ltd., China PR had requested for a review in terms of Rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping duty on dumped articles and for Determination of Injury) Rules 1995 in respect of exports being made and the Designated Authority vide notification No. 67/1/2000-DGAD dated the 7th December 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, had initiated the review on 27th August 2002 and recommended provisional assessment of all exports of Lead Acid Batteries falling under chapter 85 of Gazette schedule to the Customs Tariff Act, 1975 made by M/s. CSB Battery Guangzhou Company Ltd., China PR, as difference between the amount mentioned in Col. No. 5 and landed value of imports per Kg. of the Lead Acid Batteries till the completion of the review.

5. Further, in exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of the Rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping duty on dumped articles and for Determination of Injury) Rules 1995, the Central Government after considering the aforesaid findings of the Designated Authority, and its notification no.1/2002-Customs dated 2nd January 2002 decided that pending the outcome of the said reviews by the Designated Authority, no anti dumping duty shall be levied on exports of Lead Acid Batteries by M/s. CSB Battery Guangzhou Company Ltd., China PR when imported into India & further provided that Lead Acid Batteries exported by M/s. CSB Battery Guangzhou Company Ltd., China PR when imported into India shall be subjected to provisional assessment and a guarantee for the amount of duty calculated at the rate of as the difference between the amount mentioned in Col. No. 5 and landed value of imports per Kg. of the Lead Acid Batteries vide notification no.110/2002-Customs.

6. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said reviews by the Designated Authority, the importer should be liable to pay the amount of duty imposed on all imports into India of Lead Acid Batteries from M/s. CSB Battery Guangzhou Company Ltd., China PR from the date of initiation of said review.

7. The Authority received a request to initiate a 'new Shipper' review of notification no 67/1/2000 dated 7th December, 2001, pursuant to the Rule22 of Anti-dumping Rules, from the Chinese producer **M/s CSB Battery Co. Ltd., China PR** (hereinafter referred to as 'the company concerned'). This company claimed that it is not related to any of the exporting producers in China PR subject to the anti dumping measures in force with regard to the product concerned. Furthermore, it claimed that it has not exported the product concerned during the original period of investigation. The Authority prima-facie examined the evidence submitted by the Chinese producer concerned and considered sufficient to justify the initiation of a review in accordance with the provisions of the Rule22 of Anti-dumping Rules.

8. The product covered by the current review is the same as in the original investigation, i.e. *'lead acid batteries'*.
9. The authority sent an exporters questionnaire and also an additional questionnaire concerning their claim for Market Economy Treatment. The exporter filed the questionnaire within the extended time period. The authority sought and verified all information it deemed necessary for the purpose of determination of dumping and carried out a verification visit at the premises of the exporting producer concerned,
10. As no request for a review of the findings on injury was made in this investigation, the review is limited to determination of dumping only.
11. The investigation of dumping covered the period from 1st September 2002 to 28th February 2003.
12. The authority officially intimated the authorities of the exporting country of the initiation of the New Shipper Review and gave opportunity to all the interested parties directly concerned to make their views known in writing within 40 days from the expiry of the POI (i.e., 1st September 2002 to 28th February 2003). Subsequently the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally, in a public hearing held 27th August 2003. All the interested parties presenting their views were requested to file written submissions of the views expressed, which were filed by them.
13. The Authority made available the public file as per Rule 6(7) to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request.
14. The Authority conducted on spot verification of the data furnished by M/s CSB, China PR.
15. In accordance with Rule 16 of the anti dumping Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed on 9/12/2003 and on 3/3/2004 to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
16. **** in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules.

B. Product Under Consideration:-

17. The Authority has decided to continue with the description of product under consideration as Lead Acid Battery as determined in the original case. There is no argument on the product under consideration and like article by any of the interested parties. The Authority notes that the lead acid batteries

produced by the petitioners are 'like articles' to lead acid batteries being imported from the subject country within the meaning of the Rules.

18. In view of the foregoing the Authority holds that product under consideration in the present investigations is "industrial lead acid batteries", classifiable under Customs Tariff 8507 *within Chapter 85 of the Custom Tariff Act. The batteries are described as electric accumulators under the Customs Tariff Act and are classified under customs sub heading Nos. 8507.10 and 8507.20 of the Customs Tariff Act. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation*".

Views of Domestic Industries

19. The views of the domestic industry received after initiation of the New Shipper Review till the comments on disclosure statement have been summarized and reproduced from para 21 to 31.

20. The Companies seeking new shipper review and the companies who have exported the product under consideration are separate legal entities from different countries, both of them (countries) having their own normal value. The producer has claimed that it has not exported any material in the period originally investigated. However, the producer has not exported any material even in the present POI. The exporter being a separate legal entity in different country which has its own normal value and which is attracting anti dumping duty. Exports affected by the New Shipper can not be claimed as exports of the producer.

21. Normal value for exporter (trader) from Singapore and for the producer from China PR is different, as the two are in different countries and both countries having their own normal value. In fact, the exporter from Singapore is already attracting residual duty by virtue of the anti dumping investigation against Taiwan, Singapore and Hong Kong.

22. The trader having exported the product under consideration, has neither joined in the present petition, nor has certified that it has not exported the material in the past POI, nor has it certified that it is not related to any producer/exporter who exported in the earlier POI. In fact, the trader had exported the material in the past POI and is related to a producer who had exported the material in the past POI.

23. Rule 22 has used the words producer and exporter at the same time. It can not be argued, therefore, that the word producer and exporter imply the same meaning. Clearly, the Rules have distinguished between the two words. This is further established by the anti dumping investigations relating to CFL, wherein the Designated Authority has recommended anti dumping duty on exports from Hong Kong in spite of clear admission of the petitioner itself that Hong Kong did not produce the subject goods. At the same time, Designated

Authority has recommended separate anti dumping duty and dumping margin in respect of traders. Such being the case, it can not be claimed by the domestic industry that the trader and producer should be seen together.

24. Assuming that the word producer and exporter are required to be seen together and exports made by the exporter must be seen as exports made by the producer, it follows that producer can not claim status of new shipper, as in such an event, the producer can not satisfy that it was not related to any producer/exporter who exported the material in the previous POI.

25. While the petition was filed by producer, the questionnaire response has been filed by a trader from a different country and the petitioning producer. Thus, without any application, the trader has introduced itself at the stage of questionnaire response, that too, without any letter, authorization, and certification. In fact, it can be said that there is no legal authority for the Designated Authority to consider the information provided by the trader.

26. Such being the case, the whole investigations being conducted with regard to the two petitioning exporter are required to be terminated on the grounds,

- a) the petitioning producer do not satisfy the requirements under Rule 22;
- b) petitioning producers can not claim to have their own export price in respect of exports made in the current POI;
- c) normal value can not be determined with reference to the country of origin when the country of exports has its own normal value;
- d) Company who has exported the material has not filed any petition nor has given necessary statutory declarations as required under the Rules.

27. The exporter has taken a significant time to file its questionnaire response.

28. The period considered for the present investigation is prospective whereas in the various cases initiated earlier, the POI was fixed as a past POI for fresh investigations under Rule 5 and for Review under Rule 23. The propriety of a prospective POI is not understood by the Indian producers particularly when a future investigation period is fixed with a view to determine dumping margin in respect of such future exports. In case of prospective POI, there are greater possibilities with regard to the fact that the exporter can export the material at doctored prices to get lower dumping margin and the quantity exported may not be representative. Thus, the authority must ensure that there must be certain volumes which the exporter must have exported before dumping margin can be assessed in relation to such exports and it need to be ensured in some justiable and equitable manner that the export price is representative. Before accepting the export price, the factors such as (a) association/existence of some compensatory arrangements; (b) resale price of the product; (c) the price at

which the importer purchased like article from other sources; (d) any affiliation between the seller and buyer-legal or contractual, need be examined.

29. The exporter must satisfy on the basis of information and evidence that they satisfy the market economy treatment (MET) and the domestic industry had not received even a single document/information/evidence to justify and support their claim on this account. It was a great discovery to Indian producers at the time of public hearing that the exporter had filed some confidential documents in this regard. Non-confidential version filed by the exporter is grossly inadequate and insufficient.

30. It is the condition in a new shipper review that the exporter must not be related to an exporter/producer who has been found to have dumped the goods. The CSB has been clearly held to have exported and dumped batteries in India in the past as also in the POI selected by the authority. CSB has sold large volumes of batteries to India. It has resorted to discriminatory pricing and eventually lowered its prices to as low as US\$ 1.24/Kg (US\$ 3.35 per battery of 2.7 Kg.) This does not permit even recovery of associated direct costs. It is evident that either (a) selling price of the exporter in the domestic/third country market is higher; or (b) the exporter has suffered financial losses in the domestic/third country market. Under both the situations, dumping margin is positive and significant.

31. Once again the domestic industry in its comment on disclosure stated to terminate the investigation on the grounds of failure of the petitioner to disclose the information appropriately in the non-confidential manner. They have also stated that the normal value is required to be assessed on lines of the Non Market Economy principle and further supplemented that even they have been entitled for Market Economy Treatment, normal value should have been assessed on the basis of other responding petitioner under investigation.

Views of Exporter

32. The views of the domestic industry received after initiation of the New Shipper Review till the comments on disclosure statement have been summarized and reproduced from para 33 to 43.

33. M/s. CSB Battery Guangzhou Company Ltd., China PR was asked to file their replies to the questionnaire on the subject. In their replies, it is stated that the company has not made any exports to India prior to the period of investigation. The Indian producers do not have any locus standing to raise any objection as all the submissions were made by the exporter after seeking proper extension of time from the Authority. This is, notwithstanding the fact that no prejudice can be caused to the Indian producers as the delay in fixing the individual dumping margin can only affect the interests of the exporter. The representative of the Indian producers has not considered the fact that

extensions were taken in view of the SARS problem which prohibited people to travel in that part of China PR.

34. The representative of the Indian producers has indicated that they have gone through the earlier cases initiated by the Designated Authority and observe that the POI was earlier being fixed for the past period. The Indian producers have not indicated even one such case where the POI is for the past period only. In view of this, the argument is totally unsubstantiated and cannot be commented upon appropriately. The so-called representative of the Indian producers has also not drawn the attention of the Authority to any provision of law or even the WTO provision which contemplates or mandates only a past period in case of a New Shipper Review. The reference to Rule 5 and Rule 23 is irrelevant, as these Rules apply to a fresh investigation or a mid-term review. It may be appreciated that the New Shipper Review is carried out with a limited purpose of determining individual dumping margin for the exporter who fulfills the conditions prescribed under Article 9 (5) of the WTO Agreement or under Rule 22 of the Anti dumping Rules. In fact, this practice is followed by a large number of countries including the US, EC, Argentina, Venezuela and Brazil. Apprehensions and conjectures made by the Indian producers are of no consequence in a proceeding that is wholly in accordance with law. The suggestion by the Indian producers are wholly extraneous to the anti dumping Rules. The Hon'ble Designated Authority is bound by the provisions of the Customs Tariff Act being a creature of the same statute and has to examine the case within the provisions of Rule 22 of the Anti dumping Rules.

35. The new shipper has claimed market economy status and has submitted extensive evidence to support its case. The laws are available in public domain whereas information relating to purchase of raw material, costs, sales prices etc. are by their very nature confidential. The exporters also mentioned that they would also like to place on record that the domestic industry in the original investigation refrained from providing crucial information to other interested parties without even claiming confidentiality on the same despite repeated requests and reminders by the cooperating exporters. The domestic industry failed to provide even the details of the domestic production to support their claim of having the standing to file the petition. The Indian producers cannot claim different standards to be followed in the very same case.

36. With regard to the claim that the dumping margin for CSB is very substantial, it has been contended that the representative of the Indian producers has given some imaginary figures about the export price of CSB to India and has vaguely alleged substantial dumping by them. All these baseless allegations have been denied. The claim that they are selling below their associated direct costs is also baseless which can be verified by the Designated Authority.

37. On the issue of the need to issue preliminary findings, it has been submitted that it is a settled principle of anti dumping law that the scope of the

investigations is restricted to determination of the individual dumping margins for the applicant exporters. The demand for preliminary findings is not only against the scheme of anti dumping Rules but only an attempt by the Indian producers to delay the legitimate claim of the exporters.

38. As regards the issue raised whether individual dumping margin can be claimed by an EOU, it has been submitted that no reasoning or provision of law has been given as to why an EOU loses its claim to individual dumping margin in a New Shipper Review case. The Designated Authority itself has in a large number of cases determined separate dumping margins for cooperating exporters irrespective of whether they were export-oriented or not. Several Indian exporters (EOUs) have been successful in getting individual dumping margins in EC and other countries. This is precisely due to the fact that there is no provision which bars the determination of individual dumping margin for export-oriented units.

39. The attention of the Hon'ble Designated Authority has also been drawn on the ruling of the Hon'ble Mumbai High Court in the case of H & R Johnson Vs. Ministry of Finance and Others. This decision of the Hon'ble High Court is directly applicable to the facts of the case and the judgment of this case will be applicable to this New Shipper Review for determination of individual dumping margin.

40. On the issue of relationship of the New Shipper with the exporter who has been attracting anti dumping duty in the earlier investigations, it is submitted by the exporter that the New Shipper is required to demonstrate whether he is related to any exporter/producer in the exporting country in question. In this regard representative of the exporter has cited some of the decisions of the European Commission.

41. In the council regulation (EC) No. 496/2002 of 18th March 2002, it is inter-alia stated *"further more, according to documentary evidence submitted the company was able to satisfactorily demonstrate that it did not have any links direct or indirect, with any of the Indian exporting producer subject to the anti dumping measures in force with regard to the product concern."* The original Council Regulation No. 2604/2000 of 27th November 2000 was against various countries including India but the issue of relationship has been examined only in the context of exporting country in question in.

42. In the Council Regulation No. 2570/2000, of 20th November 2000, it was stated *"further more, according to documentary evidence submitted the company was able to satisfactorily demonstrate that it did not have any links direct or indirect, with any of the Chinese exporting producer subject to the anti dumping measures in force with regard to the product."* In the original Council Regulation No. 393/98 of 16th February 1998 states that original investigation was against

various countries including China but the issue of relationship has been examined only in context of exporting country in question.

43. The exporter has cited some more findings of European Commission wherein it is stated that the New Shipper investigation was initiated provided the company was able to satisfactorily demonstrate that it did not have any links, direct or indirect with any of the exporters/producers in the country of new Shipper subject to anti dumping measures in force with regard to the product concern. It is further stressed that the EC examined the relationship of New Shipper only with the exporter or producers from the country in question but not with the producers or exporters from subject countries to the original or any other anti dumping investigation.

C. EXAMINATION BY AUTHORITY:

44. In the instant case, the Authority had extended the time for the submission of the Exporters Questionnaire response on sufficient cause being shown by the exporter. The authority notes that the exporter had filed all the responses within the extended time. The contention of the Domestic Industry regarding the undue delay by the exporter in submitting the response does not have any merit.

45. The Designated Authority initiated new shipper review keeping in view the provisions of the anti dumping rules, which are reproduced below:

"Rule 22: (1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act, on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of initiation of the review".

46. Rule 22 clearly specifies the circumstances under which a new shipper investigation can be carried out for the purpose of calculating individual dumping margin. Individual dumping margin in respect of an exporter from the exporting country in question can be determined provided the two conditions are satisfied.

These are: (a) that the exporter has not exported during the period of investigation and, (b) that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product. The Designated Authority in the present case finds that the exporter has not exported product under consideration during the period of investigation. Individual dumping margin in respect of an exporter from the exporting country in question can be determined provided the above conditions are satisfied. The Designated Authority in the present case prima-facie on the basis of declarations of the exporter initiated the New Shipper Review

47. As regards the validity of considering a prospective period of investigation, it would be pertinent to refer to the first proviso to Rule 22(2). This proviso confers the power on the Central Government to provisionally assess the imports in the context of a new exporter if the Designated Authority so recommends. Further, it is important to note that there is nothing in Rule 22 or any other part of the anti dumping rules to suggest that the period of investigation as envisaged under Rule 22 cannot be for a prospective period. It has also been brought to the notice of the Authority that the laws and practice of other jurisdiction also support the view that there is no bar on a prospective period of investigation in case of New Shippers. Considering the above, the Authority notes that there is no infirmity in its taking the period of investigation prospective to the initiation notification. The Authority also notes that the contention of the domestic industry regarding the reference to Rule 5 and Rule 23 are irrelevant as those Rules apply to a fresh investigation or mid-term review.

48. The domestic industry has also expressed its apprehension that by taking a prospective period of investigation the exporter would be in a position to manipulate their prices resulting in lower dumping margins. The Authority finds it difficult to accept this proposition, which is based on presumptions and apprehensions. The Authority has gone into the details of the costing, prices, sales pattern, invoices etc of the exporter to arrive at the present findings which were verified during the on spot verification.

49. The Authority further examined the provisions of New Shipper Review contained in Article 9.5 of Anti Dumping Agreement and Rule 22 of the Anti Dumping Rules and notes that the relationship test has to be carried out under Article 9.5 of Agreement between exporters and the producers in the exporting country and not between exporters and producers in different exporting countries whose product is subjected to anti dumping duty. The Authority, therefore, is of the view that it may not be appropriate to exclude CSB China from New Shipper Review on the ground that it is related to CSB Singapore as new shippers relationship is to be examined in the same country, i.e, China, PR..

50. As regards, the judgment of the Hon'ble Bombay High Court in the matter of M/s. H & R Jonhson Vs. Ministry of Finance and Others, the Hon'ble Court has given guidelines on different parameters under Rule 22 regarding the declaration

of the exporter, if the producers and exporters are not from the same country. In the instant case the issue has been raised regarding the relationship of the New Shipper with the exporter in a different country who is attracting anti-dumping duty. The Authority notes that the judgment of Hon'ble High Court is not relevant in this present case.

51. (i) The Authority has examined the determination of normal value after a thorough examination and analysis of exporters information/data provided during the course of investigation and further verified and reconciled during the on-spot verification.

(ii) It has also been argued that the vital information kept confidential by the interested parties depriving the opposing interested parties of the right to challenge the information and make the meaningful submissions to the Authority. However, regarding the information being made available to the opposite interested party has been dealt as provision regarding the confidentiality. The Rule 7 of the Anti Dumping Rules provides for submission of information by the interested parties on confidential basis subject to the condition laid down therein. The non-confidential summary of the information submitted on the confidential basis is placed in the public file, which is available for the inspection, by all the interested parties in terms of Rule 6 (7) of the Anti Dumping Rules. In this case non-confidential summary of the confidential submissions made was placed in the public file accessible to the interested parties.

D. ASSESSMENT OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND METHODOLOGY FOR CALCULATION OF DUMPING MARGIN

Views of Domestic Industry

52. The present investigation is required to be conducted in accordance with the amended Rules on NME. The exporter must satisfy on the basis of information/evidence that they satisfy the Market Economy Treatment. The non-confidential version of the exporter is grossly inadequate and insufficient to allow any understanding of the substance of information filed by the exporter. They have further submitted that several decisions of the EC wherein the claim of Market Economy Treatment has been rejected on the ground even if few of the conditions laid down under the rules are not satisfied.

Views of Exporter

53. The exporter in this case has claimed Market Economy status and has submitted extensive evidence in that support. The Laws are available in the public domain whereas information relating to purchase of raw materials, costs, sales prices etc. by their very nature are confidential. They have produced the details on each and every parameter with supporting document for their claim to

treat them as Market Economy and determine the normal value as per the Para 1 to 6 of Annexure I of Anti Dumping Rules.

Examination by the Authority

54. In the instance case, China is proposed to be investigated a non-market economy. Petitioner in the original investigation has claimed that European Commission and United States have treated China as non-market economy in the past three years. Therefore, determination of normal value in respect of China is to be done in accordance with the Rules relating to non-market economies as contained in Para 7 & 8 of Annexure-1 of Rules as amended vide Notification dated 4.1.2002.

55. As communicated to the exporter and to the Embassy of China, the Authority proposed to examine the determination of normal value in the light of Para 7 & 8 of Annexure 1 of anti dumping Rules as amended. The Authority notes that para 7 of Annexure 1 of anti dumping rules, *inter-alia* provides that:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin....."

Further Para 8 of Annexure 1 of the Rules Supra (as amended) provides that:

"8 (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph(3)

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economic country,

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

56. *The Authority notes that the exporter has furnished necessary information/ evidence as mentioned in sub Para 3 of the Paragraph 8 of Annexure 1 of anti dumping Rules to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether*

- a) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials cost of technology and labour, output sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the Designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph.

57. In proceedings involving Non-Market Economy countries the Authority begins with a presumption that all companies within the country are subject to Government control and thus should be assigned a single anti dumping rate unless an exporter can affirmatively demonstrate in absence of government control both in Law and in fact with respects to its sales – both domestic and export. In this review the new shipper M/s CSB China PR has requested for a company specific determination.

58. Whether a company is sufficiently independent in its export activities from government control to be entitled for a separate, company specific rate, the Authority examined the exporting entity in a NME country under test established as per anti dumping rules. The Authorities individual treatment test is unconcerned with macro economic/border type controls like export licenses quotas and minimum export prices particularly if these controls are imposed to prevent dumping. Rather the Authority focuses the examination on control over investment, pricing and decision making process at the individual company specific level. Accordingly the Authority analyzed to determine whether this producer/exporter is independent from government control or not.

59. The Authority considers the following criteria in determining whether an individual company may be granted a separate rate due to prevalence of market economy,

- i) an absence of restrictive stipulations associated with an individual exporters business and export licenses
- ii) any legislative enactments decentralizing control of companies, and
- iii) any other formal measures by the Government decentralizing control of companies,

60) CSB China has placed number of documents to demonstrate absence of State interference and control i.e., company law, labour law, joint venture law and accounting rules or law. The Authority examined,

i) Whether a respondent is subject to government control in their sales and procurement activities,

- i) whether the export price is set by or subject to the approval of a governmental authority,
- ii) whether the respondent has authority to negotiate and signed contracts and other agreements,
- iii) whether the respondent has autonomy from the government in making decisions regarding the selection of its management and
- iv) finally whether the respondent retains the proceeds of its export sales and makes independent decisions regarding disposition of profits or financing of losses
- v) The company was able to show to satisfaction of the Authority that management and control of the factory regarding production, marketing and pricing were in the hands of the management of the company, which were significantly independent from the state intervention.

61. According to the New Shipper, it is a limited company under the Law of People's Republic of China on foreign capital enterprises and there has been no change in its legal form since its inception. They have further stressed that there is no government participation in finalizing by export/domestic price. The management is free to finalize the sales contracts. There is no binding on the Authority/management to notify any government authorities regarding the selection in their management. The company is free to decide regarding its use of revenue without taking permission or intimating the government. The Authority notes that the analysis of the details furnished by the exporter does not reveal existence of government control.

62. During the course of verification the data furnished were verified and reconciled with their accounts and as regards the existence of state interference. The Authority observed that Govt. of China is not influencing in taking decision

relating to inputs, selling price/costs etc. as envisaged in paragraph 8(3)(a) of Annexure I of anti-dumping rules.

63. The Authority on the basis of examination of the pricing and cost of raw material, it is found that no production cost and financial situation of the company was found to reflect any distortion as verified from their books of accounts, articles of association etc.

64. The bankruptcy and property laws were also discussed and found that the companies in China are free to acquire property, however in the government specified area the law of the territory is regulated on the industries. The bankruptcy law is applicable to a firm when a firm become bankrupt and the details regarding the settlement of the dues is governed by law maintained under bankruptcy law.

65. The exchange rate conversions were also verified from their books of accounts and the export transactions. The Authority notes that all conversions have taken place on the existing rate, which is more or less stable without much fluctuation.

66. The authority also notes that the company is free to purchase, raw and semi process materials, fuels and other materials either in China or source it from other parts of the World. Presently the company is buying major raw material i.e., Lead from Australia, Taiwan and Korea while the rest is bought in China itself. It is further seen that they have procured the lead at different rates from different sources and it has been bought from different suppliers at the internationally prevailing prices.

67. Electricity is procured from the electric company owned by local authorities. Gas is supplied by a private company and the average rate of purchase is RMB 10.3716 per cubic metre.

68. All the employment decisions are taken by the company and employees are hired through news paper advertisement, private employment agencies etc. There is a full freedom to the company with regard to its mode of hiring employees and the average salary paid to the different classes of workers is given along with the performance incentive. The Chinese Government does not provide any benefit like housing, medical care etc. but the company provides accommodation to all and the cost of the same reflected in the books of accounts as an expense.

69. There are no sales in the domestic market of the subject goods. There is no state involvement in price/quantities and all such decisions are taken on purely commercial basis. There is no price list either for domestic or export as it varies from customer to customer and reflected on the basis of demand and supply position in the market.

70. The books and records of the company are maintained in mandarin and figures are denoted in Renmin (RMB). The accounting rules and the principle applicable to the foreign joint venture are as per the law. The accounting standards and rules are prescribed by Ministry of Finance of People's Republic of China.

71. All assets of company have been obtained from the open market on purely commercial basis. No assets were provided by the state or any third company free or on other than commercial principles. All assets other than the land are owned by the company whereas land has been obtained on a long term lease of 15 years. The company has fully been financed by the shareholders. There is no subsidy scheme either for loans or electricity supply of which the benefit is available to the company.

72. There is no restriction on the company with regard to foreign exchange transactions. There is one single exchange rate for purchase of inputs, conversion of the proceeds of export sales and repatriation of profits. The profit is distributed among the shareholders in accordance with the accounting regulations and there is no restriction on the distribution/repatriation of the profits for the capital invested.

73. The Authority in view of the information provided by the exporter on the issue of market economy with evidence in the light of Custom Notification No. 28/2001 dated 31st May 2001 and No. 1/2002 dated 4th January 2002 on the anti dumping in respect of issue of Market Economy under anti dumping Rules Supra and the fact that the cost of production of the subject goods as per market forces has been made available by the exporter hence the Authority considers to treat this individual exporter operating in the market economy. During the course of meeting with the officials of MOFCOM (Ministry of Commerce of the People's Republic of China, it was conveyed that there is no controls of state in the matter of its operation and management which was actually verified with the records available with the exporter. The company was able to show to satisfaction of the Authority that management and control of the factory regarding production, marketing and pricing were in the hands of the management, which were significantly independent from the state intervention. In the light of above examination it was considered to grant Market Economy treatment to the new shipper and determine normal value in line with para 1 to 6 of Annexure 1 to the Anti Dumping Rule.

74. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or

- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –
- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

NORMAL VALUE:

75. The Authority sent exporter questionnaire to M/s CSB Guangzhou Battery Co. Ltd., for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1) (c) of the Custom Tariff Act. In response to the questionnaire M/s. CSB Guangzhou Battery Co. Ltd., submitted the information in exporter questionnaire. Since the company does not sell the subject goods in the domestic market, the normal value is either to be assessed based on exports to appropriate third country or the cost of production plus reasonable return. As the export to third countries were loss making transactions the Authority disregarded it for the purpose of determination of normal value and went ahead with the methodology of cost of production with reasonable returns. The company has provided details of cost of production of different models of batteries sold to India and the same forms basis for assessing normal value for the exporter. The exporter has also furnished the cost of production of different types of industrial batteries as per Appendix –8,9 and 10 . Further, during the course of verification the exporters was asked to explain the cost of production indicated in Appendix-8,9 and 10 and reconcile the same with the books of accounts/ profit and loss account for the period of investigation. However, it was explained by the exporter that the cost of production so indicated in these appendices is based on actual.

76. The exporter has furnished detailed cost of production of the different models of lead acid batteries produced during the period of investigation. Profit & loss account of the company has also been furnished on monthly basis for the period of investigation. The exporter provided reconciliation of the cost of production with the books of accounts/ profit & loss account for the period of investigation. It was found that the cost of production as reflected in the cost statement and as assessed during the verification, taking into consideration the cost as per profit & loss account, there is an under absorption of expenses to the extent of 6.07%. The same has been duly accounted for while assessing the cost of production of the subject goods for the period of investigation.

77. The company has exported three models of Industrial batteries to India during the period of investigation. The battery wise ex-factory normal value is referenced as ****, ****, and ****US\$ per battery of the Industrial Lead Acid Batteries.

EXPORT PRICE:

78. In response to the questionnaire, the exporter has furnished invoice-wise/ model-wise details of exports made to India during the period of investigation in Appendix-2. The exporter has also furnished sample copies of invoices in support of the same. The exporter has exported maintenance free industrial lead acid batteries to India during the period of investigation. Adjustment as claimed by the exporter in Appendix-4 with regard to inland freight, storage handling, insurance, shipping charges etc., have been considered after duly verified and allowed to arrive at the ex-factory export price to India. During the course of on-spot verification at their premises, it was found that the export to India by M/s CSB, China PR are carried out through CVI Logistics Corporation (CVI), British virgin Islands and CVI further sold the goods to CSB Battery (Singapore) Ptr Ltd., (CBS) who finally exported the goods to India.

79. All adjustments have been calculated backwardly to arrive at the net export price. In this regard the invoices pertaining to CBS China to CVI British Virgin Islands and CVI to CBS Singapore and finally CBS Singapore to Indian customers were verified and reconciled along with the adjustments claimed by them. The details regarding their adjustments were verified and reconciled from the original records available with the company.

80. The battery wise export price comes to US \$****, ****, **** per battery of industrial lead acid battery exported to India by the company during the period of investigation.

DUMPING MARGIN:

81. As there is a wide variety of models and types of batteries, these need to be brought into a common denominator for the purpose of calculation and comparison. As mentioned above, there is a direct co-relation between power, lead content and weight of the battery, which also gets reflected in terms of value or price. Further, the direct co-relation between the lead content and weight of the battery and its associated costs and prices is also quite significant. The Authority, therefore, considers denoting the normal value as well as the export price in terms of weight of the batteries for the purpose of their comparison and arriving at a dumping margin. The weight has been considered based on the technical details furnished by the exporter and verified during the course of investigation. Considering the normal value and export price as detailed above, dumping margin has been determined as, 12.31%

E. Final Findings of the Review

82. After considering the foregoing the Authority concludes that

i) Lead Acid Batteries exported to India from M/s CSB China PR is below its normal value during the period of investigation,

ii) The Authority recommends imposition of definitive anti dumping duty on all imports of lead acid batteries falling under Custom Code 8507 originating in or exported by M/s CSB China PR. Anti dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in Column no 9 of the following table and landed value of import per kg of the lead acid battery exported/manufactured by M/s CSB China PR and this shall be leviable from the date of initiation notification to be issued in this regard as per para 22(2) of the anti dumping rules by the Central Government on all imports of lead acid batteries falling under Custom Code 8507 originating in or exported by M/s CSB China PR.

TABLE

Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Reference price (US\$)	Unit of Measurement	Currency
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8507	Lead Acid Batteries		China PR	China PR	M/s. CSB Battery Guangzhou Co., Ltd.,	M/s. CSB Battery Guangzhou Co. Ltd.,	1.956	Kg.	US Dollar
8507	Lead Acid Batteries		China PR	Singapore	M/s. CSB Battery Guangzhou Co., Ltd.,	M/s. CSB Battery Guangzhou Co., Ltd.,	1.956	Kg.	US Dollar
8507	Lead Acid Batteries		China PR	China PR	M/s. CSB Battery Guangzhou Co., Ltd.,	M/s. CSB Singapore	1.956	Kg.	US Dollar
8507	Lead Acid Batteries		China PR	Singapore	M/s. CSB Battery Guangzhou Co., Ltd.,	M/s. CSB Singapore	1.956	Kg.	US Dollar

iii) Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

iv) An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority